

प्रेषक,

एन०एस०न०पलच्याल,
प्रमुख राशिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

राजस्व विभाग

देहरादून: दिनांक: 19 फरवरी, 2008

विषय:-

मै० मुल्तानी फार्मास्यूटिकल्स लि० को फार्मास्यूटिकल फार्म्युलेशन उद्योग की स्थापना हेतु मै० स्पीड लाईफ साइन्स इंक मक्खनपुर महमूद आलग मु० तहसील रुड़की की कुल 0.37137 है० भूमि क्रय करने की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1309/भूमि व्यवस्था-भूमि क्रय दिनांक 8-12-2007 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय मै० मुल्तानी फार्मास्यूटिकल्स लि० को फार्मास्यूटिकल फार्म्युलेशन आदि उद्योग की स्थापना हेतु उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विन्यास एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक 15-1-2004 की धारा-154(4)(3)(क)(V) के अन्तर्गत मै० स्पीड लाईफ साइन्स इंक मक्खनपुर महमूद आलग मु० तहसील रुड़की की कुल 0.37137 है० भूमि क्रय करने की अनुमति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैं:-

- 1- कंता धारा-129-ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलेक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि क्रय करने के लिये अर्ह होगा।
- 2- कंता बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिये अपनी भूमि बन्धक या दृष्टि बन्धित कर सकेगा तथा धारा-129 के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।
- 3- कंता द्वारा क्रय की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में

.....(2)

अगिहिशित किया जायेगा, उसी प्रयोजन के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गई है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ कय किया गया था उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा-167 के परिणाम लागू होंगे।

4- जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि कय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

5- जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसका भूस्वामी अरांकगणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

6- शासन द्वारा दी गई भूमि कय की अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी एवं भूमि का कब्जा प्राप्त होने के 2 वर्ष के भीतर निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जाये।

7- कय की जाने वाली भूमि का भू-उपयोग यदि औद्योगिक से भिन्न हो तो उसे नियमानुसार औद्योगिक में परिवर्तित कराकर शासन द्वारा निर्धारित नीति/मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अन्तर्गत प्रचलित नियमों/मानकों एवं भवन उपविधियों के अन्तर्गत प्रचलित नियमों/मानकों एवं भवन उपविधियों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही करते हुये औद्योगिक प्रयोजन हेतु भवन निर्माण का प्लान सक्षम अधिकारी से स्वीकृत कराने के पश्चात ही स्थल पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। निर्माण कार्य में स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट अथारिटी के मानकों का अनुपालन किया जायेगा।

8- कम्पनी द्वारा प्रस्तावित फार्मास्यूटिकल फार्म्युलेशन उद्योग में उत्तराखण्ड मूल के रोजगारों को नियमित रूप से न्यूनतम 70 प्रतिशत से अधिक का रोजगार दिया जायेगा।

9- कय की जाने वाली भूमि का उपयोग फार्मास्यूटिकल फार्म्युलेशन उद्योग की स्थापना हेतु ही किया जायेगा।

10- किसी भी दशा में प्रस्तावित कंटेनरों के अतिरिक्त अन्य भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी एवं सार्वजनिक उपयोग कोई भूमि या अन्य कोई भूमि पर कब्जा न हो इसके लिये भूमि कय के तत्काल बाद उसका सीमांकन कर लिया जाये।

11- भूमि का विक्रय अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त अनुमत्त नहीं होगा एवं ऐसी-
दशा में विक्रय किये जाने हेतु सफाई शर्तों का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

12- निर्माण के पूर्व सभी विधिक व अन्य अनापत्तियां/स्वीकृतियां प्राप्त कर ली जायेंगी।

13- उक्त शर्तों/प्रतिबन्धों का उल्लंघन होने पर अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे
शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एन0एस0नपलव्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं तारीख।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून
- 2- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 3- प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- सचिव, श्रम एवं सेवायोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 5- श्री जे0पी0पाण्डे, निदेशक, मै0 मुल्तानी फार्मास्यूटिकल्स लि0 एच-36 कनाट प्लेरा,
नई दिल्ली-1
- 6- निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, सचिवालय।
- 7- गार्ड फाईल।

आज्ञा रो,
(सन्तोष खड्गानी)
अनुसचिव।